जनादेशः 17वीं लोकसभा

ऋतेश भारद्वाज

लोकसभा चुनाव 2019 के जनादेश को देखने पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि देश भर में भाजपा का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। राजनीतिक रूप से वर्ष 2019 में तीन क्षेत्रों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा। विशेषकर उत्तर और पश्चिमी भारत में, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी इसने बड़ी सेंध लगा दी है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के चुनाव में भी सशक्त दिखाई दी। हालांकि भाजपा ने कर्नाटक में भी शानदार प्रदर्शन करते हुये 28 में से 25 सीटें जीत ली हैं और वह भी तब, जब वहाँ कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन चुनाव मैदान में था। इसके अलावा, तेलंगाना में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अलबत्ता, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भाजपा के लिये सीट जीतना संभव न हो सका। पश्चिमी बंगाल, उड़ीशा और तेलंगाना और कुछ हद तक आंध्रप्रदेश में खंडित जनादेश तथा तमिलनाडु में द्रमुक (द्रविड़, मुन्नेत्र कडघम) के शानदार प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि चुनाव अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के बावजूद राज्य स्तर पर मतदाताओं की पसंद न पसंद आज भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है। इस बार भारत की जनता ने अन्य बातों से प्रभावित होने की बजाये राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के लिये वोट किया है। राष्ट्रवाद की

भावना, जो देश में पुलवामा और बालाकोट के बाद एकदम से लोगों के मस्तिष्क में घर करने लगी, ने उन तमाम स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया, जिसने 2018 के अंतिम और 2019 के प्रारंभिक महीनों महीनों तक हिंदी पट्टी के मतदाता के लिये बहुत अजीज थी। आज कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की घटना ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया है। बेरोजगारी और ग्रामीण असंतोष की स्थिति को जनादेश ओझल नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रवाद ने अकेले इन मुद्दों को कुछ समय के लिये महत्त्वहीन बना दिया था।

वर्ष 2019 के लोकसभा में चुनाव ने 2014 के चुनाव की तुलना में कहीं ज्यादा वोट भाजपा के पक्ष में रहा। उड़ीसा के खंडित जनादेश में जहाँ लोगों ने बीजेडी (बीजू जनता दल) को फिर से सत्तारूढ़ कर दिया लेकिन भाजपा को संसद में भेजने के लिये बढ़चढ़ कर मतदान भी किया। हिन्दी भाषा वाले तमाम राज्यों मे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के गठबंधनों ने उत्तर प्रदेश व बिहार के अलावा, कर्नाटक, झारखण्ड व महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य सूबों में खराब प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि अनेक क्षेत्रीय दल लोगों को लामबंद करने में नाकाम रहे हैं। भाजपा ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतीं और कुल पड़े मतों का 37.4 प्रतिशत मत जुटाये जो कि 2014 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भाजपा ने अपने गठबंधन एनडीए के जहाँ 2014 में 336 सीटें जीतीं थीं, वहीं 2019 में इनका

आँकड़ा 351 पर पहुँच गया है। इसका मत प्रतिशत भी (सहयोगी दलों को मिलाकर) 2014 के 29 से बढ़कर 2019 में 44.9 हो गया है।[1] गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र अनेक ऐसे राज्य है, जहाँ भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुये अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया है। दक्षिण भारत में अच्छे प्रदर्शन के लिहाज से कर्नाटक मे इसने 51.38 मत प्रतिशत और 26 सीटें हासिल की और तेलंगाना में 4 सीटें जीत कर सबको हैरत में डाल दिया। इन नतीजों को देखकर यह कहना उचित होगा कि भाजपा अब एक सशक्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। यदि राजनैतिक आलोचना व सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस बात का भी संकेत मिलता है कि नकारात्मक प्रचार अभियान जैसे राफेल डील और भ्रष्टाचार के मुद्दों की भी एक सीमा होती है। भाजपा न केवल उच्चवर्गीय मतदाताओं के पारंपरिक जनाधार को बनाये रखा, बल्कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में भी उसने अपना नया जनाधार तैयार किया है।[2]

तालिका 1: 2014 व 2019 लोकसभा चुनावो में सीटों का वर्गीकरण

दल	2019	2014
भाजपा	303	282
कंग्रेस	52	44
द्रमुक	23	00

तृणमूल कांग्रेस	22	34
वाईएसआरसीपी	22	09
शिवसेना	18	18
जनता दल (यू)	16	02
बसपा	10	00
टीआरएस	09	11
लेजपा	06	06
एनसीपी	05	06
सपा	05	05
सीपीआईएम	03	09

स्रोत: कुमार संजय, कामकाज से ज्यादा राष्ट्रवाद पर वोट, राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, दिनांक 25 मई 2019, पृष्ठ संख्या 1.

तालिका 2: 2014 और 2019 लोकसभा चुनावो मे प्राप्त मतों का प्रतिशत

गठबंधन	2019	2014
श्राजग	44.9	39
यूपीए	26.53	23
महागठबंधन	6.12	-
अन्य	22.45	37

स्रोत: कुमार संजय, कामकाज से ज्यादा राष्ट्रवाद पर वोट, राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, दिनांक 25 मई 2019, पृष्ठ संख्या 1.

महिला प्रतिनिधित्व व सहभागिता

17वीं लोकसभा के जनादेश से जो सांसद इस बार चुनकर आये हैं उनके बारे में अध्ययन करने पर कई दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। वर्ष 2019 में महिला सांसदों की संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। जहाँ वर्ष 2014 में 62 महिलायें संसद पहुँची थीं तो आज इनकी संख्या 78 हो गई है। इस वर्ष चुनाव में 7334 पुरुष उम्मीदवार थे तो वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या 715 थी।[3] यदि दुनिया भर के आँकड़ों पर नजर डाली जाये तो भारत में महिला सांसदों का आँकड़ा सबसे कम है। भारत में सभी सांसदों की संख्या का केवल 14 प्रतिशत महिला सांसद हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह 43 प्रतिशत, ब्रिटेन में 32 प्रतिशत, अमेरिका में 24 प्रतिशत, रवांडा में 61 प्रतिशत और बांग्लादेश में 21 प्रतिशत महिला सांसद हैं। राजनीतिक दलों के संदर्भ में महिला सांसदों की सहभागिता या प्रतिनिधित्व को देखा जाये तो बीजू जनता दल (बीजेडी) देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 33 प्रतिशत सीटें टिकट बंटवारे में महिलाओं को देते हुये 7 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारी थी। इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस ने की 42 में से 17 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने 423 में से 54

महिलाओं को और भाजपा ने 437 में से 53 महिलाओं को टिकट दिया था।[4]

धन-बल का प्रभाव

आज लोकसभा चुनावों में धन-बल का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है विभिन्न विश्लेषकों और शोध समूहों का आंकलन है कि इन चुनावों पर राजनीतिक दलों द्वारा 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं[5] यह खर्च अब तक चुनावों में किए गए खर्चों में सबसे अधिक है, जिसमें भाजपा द्वारा इसका 45 प्रतिशत खर्च किया गया है। यह राशि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से भी अधिक है। आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि हम अभी भी विकासशील देश हैं और जुलाई-अगस्त 2019 की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। निर्वाचन आयोग भी चुनावों पर खर्चा करता है, खासकर सुरक्षा बलों की तैनाती में। इस वर्ष लोकसभा चुनावों में अप्रैल 2019 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग 700 करोड़ रुपये की नकदी जब्त कर चुका है। यह बेहद मामूली राशि है क्योंकि समुचित चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली राशि का जब्त किया जाना संभव नहीं है। बहरहाल वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2019 में जब्त किया गया धन कहीं अधिक है। हम सभी जानते हैं कि वैध सीमा से ऊपर चुनावों पर खर्च किया जाने वाला धन अवैध होता है और जन-

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के खिलाफ है। चुनावों मे धन खर्च को लेकर कुछेक नियम हैं। लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार मात्र 70 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकता है और यह सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करके निर्धारित किया गया है।

एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफाॅर्मस (एडीआर) के 15 वर्षों के आँकड़ों से चुनाव में धन की ताकत का पता चलता है। वर्ष 2014 में किसी उम्मीदवार द्वारा घाषित परिसम्पत्ति 3.16 करोड़ रुपये थी लेकिन निर्वाचित सांसदों की घोषित औसत परिसम्पत्ति 14 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।[6] इसलिये जिनके पास ज्यादा धन होता है वे चुनाव भी जीतते हैं (कुछेक अपवाद छोड़कर)। इस वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 542 में से 475 सांसद करोड़पति सांसद हैं अर्थात् 88 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं जिसमें भाजपा 265, कांग्रेस 43, डीएमके के 22, तृणमूल के 20, वाईआरएससी ;ल्त्ैब्द्ध पार्टी से 19 सांसद, शिवसेना के 18 और जेडीयू के 15 सांसद। यदि अपराधिक मामलों की बात की जाये तो कुल 542 में से 233 सांसदों पर अपराधिक मुकद्दमे हैं, अर्थात् 43 प्रतिशत सांसदों पर अपराधिक मुकद्दमे दर्ज है जबकि 2014 में 34 प्रतिशत सांसदों पर मुकदमे थे और इनमें से 29 फीसदी पर गंभीर आरोप हैं और 11 फीसदी पर हत्या का मामला दर्ज है, जिन सांसदों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें से 116 भाजपा के, 29 कांग्रेस, 10

डीएमके, 10 वाईएसआरसी और 9 सांसद तृणमूल के हैं।[7] भारतीय राजनीति में बढ़ता धन-बल और अपराधीकरण दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के लिये घातक है।

विपक्षी दलों की स्थिति

17वीं लोकसभा में यदि विपक्षी दलों की स्थिति पर गौर किया जाये तो यह कहना स्वाभाविक होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का सक्रिय होना और समर्थवान होना एक अनिवार्य शर्त है। लोकसभा के प्रथम सत्रारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के संदर्भ में कहा था, कि उन्हें अपनी संख्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका हर शब्द सरकार के लिये मूल्यवान है। आज कांग्रेस गठबंधन को 91 और अन्य दलों को 98 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 10 फीसद सीट नहीं प्राप्त कर पाने के कारण विपक्ष की कुर्सी पाने से विलग रही और उसे महज 52 सीटों से संतोष करना पड़ा परन्तु इसके गठबंधन में 91 लोकसभा सदस्य हैं। वैसे अन्य दलों के भी 98 सदस्य हैं जो भाजपा के खिलाफ जीतकर आये हैं। संसद में विपक्षी दल कांग्रेस को संख्या की चिंता नहीं कर डा. राममनोहर लोहिया की सदन में भूमिका को याद करना चाहिये। संख्या की चिंता किये बगैर डा. लोहिया सदन में अकेले मुद्दों पर तत्कालीन सरकार को घेरते थे। उनका तीन आना बनाम 25 हजार का सवाल आज भी चर्चा का विषय है क्योंकि उन्होंने सदन में पर्चा बाँट कर कहा था कि नेहरु का प्रतिदिन का खर्च 25 हजार रुपया है, जबकि

आम आदमी को तीन आना प्रतिदिन पर गुजर-बसर करना पड़ता है और बहस के बाद नेहरु को स्वीकार करना पड़ा था कि आम जन उपेक्षित है। आज विपक्षी दलों को यह सोचना होगा कि वे किस प्रकार आज की चुनौतियों का सामना करेगा। संसद में विपक्ष की भूमिका के संदर्भ में हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री धूमिल ने लिखा था कि ''एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न ही रोटी खाता है बल्कि रोटी से खेलता है।''[8] इसलिये इन परिस्थितियों में बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस और अन्य दलों को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी।

लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे खराब स्थिति वामदलों की रही। पूरे देश से केवल एक वाम उम्मीदवार विजय हुआ। पिछले 70 सालों में वाम दलों की यह सबसे बड़ी पराजय है। यही वामदल 70 के दशक तक संसद में मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था और 2019 तक आते-आते बिल्कुल ही अप्रासंगिक बनकर रह गया। पश्चिमी बंगाल में 3 दशकों तक सत्ता में रही कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी इस बार चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई जबकि केरल में इसे केवल एक सीट प्राप्त हुई। दरअसल पश्चिमी बंगाल में सीपीआई कैडर के मन में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इतना रोष था कि उन्होंने भाजपा को समर्थन देना उचित समझा क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने भाजपा को समर्थन दे

दिया। चूंकि पश्चिमी बंगाल में ममता सीपीएम को सत्ता से हटाने में कामयाब हुई थी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प होती रही थी इसलिये इन्होंने तृणमूल को पराजित करने के उद्देश्य से भाजपा को समर्थन देना ही उचित समझा। केरल के कई सीपीएम नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके कैडरों ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) को छोड़कर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाईटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट को वोट दिया।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन राजनीति की सीमाओं और सम्भावनाओं पर बात करने का सामान्य ढंग से कोई मतलब नहीं लगता लेकिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में गठबंधनों की जो हालत हुई है, वह विचारणीय है। बिहार में एक गठबंधन फेल हुआ तो दूसरा जबरदस्त रूप से सफल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन विश्लेषण का विषय होना चाहिये। मायावती को इस बात के लिये जिम्मेदार माना जाता है कि उन्होंने इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं होने दिया अगर कुछ सीटें देकर भी कांग्रेस को साथ में ले लिया होता तो हवा का रुख बदल जाता। परन्तु 17वीं लोकसभा के जनादेश की जो हवा चली वह यही बताती है कि कांग्रेस के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और बिहार में कांग्रेस के रहते भी महागठबंधन की हालत उत्तर प्रदेश के गठबंधन से भी बुरी हो गई। 17वीं लोकसभा के जनादेश पर यदि गौर

किया जाये तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि क्षेत्रीय दलों की ताकत निर्णायक रूप से कम हो गई है। क्षेत्रीय दलों की हालत यह है कि उन्हें चाहिये तो सारी सत्ता और जिम्मेदारी बहुत सीमित। मायावती के सामने किसी को भी चप्पल-जूते पहन कर आने की इजाजत नहीं है पर 30 साल से जारी भूमण्डलीकरण पर, विदेश नीति पर, खेल नीति पर उनकी क्या राय है, किसी को पता हो तो बताएँ?

यदि 17वीं लोकसभा के चुनावों में दिये गये जनादेश पर देखा जाये तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह चुनाव मुख्यतः राष्ट्रवाद के नाम पर जीता गया, जिसमें महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में धन का अप्रत्याशित उपयोग किया गया। परन्तु इसके बावजूद कुछ सामाजिक व आर्थिक विषयों की अनदेखी भी की गई जैसे इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल द्वारा प्रदूषण, जल संरक्षण नीति, महिलाओं के ज्वलंत मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाओं, जनसंख्या नियंत्रण व राजनीति में बढ़ते आपराधीकरण को लेकर कोई प्रत्यक्ष व व्यापक घोषणायें मैनिफेस्टो में नहीं की गई। आज लोकतंत्र को यदि सही अर्थों में राष्ट्र के हित में लगाना है तो स्पष्ट व उच्च राजनैतिक इच्छा और सत्ता के लालच से ऊपर उठकर आम नागरिकों के हित में कुछ ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और इसके लिये ईमानदारी से चुनाव सुधारों को लागू किया जाना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ

[1] कुमार संजय, कामकाज से ज्यादा राष्ट्रवाद पर वोट, *राष्ट्रीय सहारा*, हस्तक्षेप, दिनांक 25 मई 2019, पृष्ठ संख्या 1.

[2] *वही*

[3] https://www.news18.com/news/india/17th-lok-sabha-will-have-a-record-78-women-parliamentarians-but-equal-representation-is-still-far-from-reality-2159337.html, Dated 22.08.2019 at 11.15 am.

[4] https://www.jagran.com/elections/lok-sabha-smriti-irani-and-gautam-gambhir-among-300-mps-elected-for-first-time-in-lok-sabha-election-2019-jagran-special-19253413.html,dated 22.08.20192019 at 12.00 pm.

[5] https://www.news18.com/news/politics/with-about-rs-100-cr-spent-in-each-ls-constituency-we-just-witnessed-the-most-expensive-election-ever-2171789.html,Dated 23.08.2019, at 11.19 am.

[6] शास्त्री त्रिलोचन, चुनावों मे धन बल, *राष्ट्रीय सहारा*, हस्तक्षेप, दिनांक 20 अप्रेल 2019, पृष्ठ संख्या 1

[7] https://web.dailyhunt.in/news/india/urdu/lokmat+news+hindiepaperlokmhin/lokasabha+chunavah+542+sansado+me+se+233+ke+khilaph+aaparadhik+mukadame+159+ke+khilaph+gambhir-newsid-117170663, dated 23.08.2019 at 12.30 pm

[8] किशोर आनन्द, कांग्रेस के बदलने से ही बनेगी बात, *राष्ट्रीय सहारा*, हस्तक्षेप दिनांक 27 जुलाई 2019, पृष्ठ संख्या 3.